भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1821
7 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

बांध क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में मछली पालन

1821 डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेष रूप से बांध क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में मछली पालन और इसके परिणामस्वरूप सरकारों के लिए राजस्व सृजन की अत्यधिक संभावना है, यदि हां, आज की तिथि तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य सरकारों और विभिन्न हितधारकों के परामर्श से इस संबंध में कोई विशेष नीति बनाने पर विचार करेगी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग): 33 लाख हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र में फैले जलाशयों की विशाल अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए और इस क्षमता का उपयोग करने के लिए के मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कई पहल और नीतियां लागू की गई हैं । जलाशयों के एकीकृत (इंटीग्रेटेड) विकास पर जोर देने और ऊपरी क्षेत्रों (अपस्ट्रीम) सहित मत्स्य संसाधनों का उपयोग करने के लिए, 2015-16 से 2019-20 के दौरान कार्यान्वित नीली क्रांति पर केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जलाशयों में मछलियों के केज आधारित पालन और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों की गुणवत्ता वाले फिंगरलिंग्स को जलाशयों में स्टॉक (भंडारण) करने के लिए 420.36 करोड़ रुपए के परिव्यय से कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई थी । इसके अलावा, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने पीएमएमएसवाई के तहत विगत चार वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2023-24) के दौरान और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2024-25) में 1809.23 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय पर 50,710 जलाशय केजों की स्थापना, 27 जलाशयों के एकीकृत विकास और 4.17 लाख हेक्टेयर जलाशय क्षेत्र में फिंगरलिंग्स के भंडारण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है ।

जलाशय जल संसाधनों का प्रबंधन और विनियमन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और कई राज्य सरकारें अपनी स्वयं की जलाशय मात्स्यिकी नीति लागू कर रही हैं । मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जलाशय मात्स्यिकी संसाधन विकास के लिए राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रहा है ।

*****